भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 376
जिसका उत्तर मंगलवार 18 जुलाई, 2017 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु लिथियम आयन बैटरियां

376. श्रीमती के मरगथम:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करने हेतु लिथियम आयन बैटरी बनाने हेतु सुविधाएं स्थापित करने के लिए विनिर्माताओं को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी सुविधाओं की स्थापना हेतु इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): फिलहाल, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम करने के लिए लिथियम आयन बैटरियां बनाने हेतु सुविधाएं स्थापित करने के लिए विनिर्माताओं को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव भारी उद्योग विभाग में विचाराधीन नहीं है।

तथापि, भारी उद्योग विभाग को भारत में बैटरी पैक हेतु एकीकृत विनिर्माण सुविधा स्थापित करने हेतु प्रोत्साहनों के संबंध में प्रबंध निदेशक, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से परामर्श करके प्रस्ताव की जांच के बाद, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को सूचित किया गया था कि यदि उनके उत्पाद का ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकी में प्रयोग किया जाता है, तो एमईआईटीवाई की मॉडीफाइड स्पेशलइंसेंटिव पैकेज स्कीम (एम-एसआईपीएस) के तहत प्रोत्साहन देने हेतु विचार किया जा सकता है। उनको यह भी सूचित किया गया है कि इस संबंध में अंतिम निर्णय एमईआईटीवाई को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्ताव दिए जाने के बाद एम-एसआईपीएस की मूल्यांकन समिति द्वारा विस्तृत मूल्यांकन के दौरान लिया जाएगा।

*****